(1600/VR/SK)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Thank you, Madam. I would like to draw the attention of the House to a very important issue related to COVID-19. From being lauded having the best response to the pandemic in the country, Kerala has now become one of the worst COVID-19-hit States. While the Coronavirus is showing a downward trend in most of the States, Kerala is among the few States that continue to be a case of concern. Kerala presently has the most COVID-19 patients with Ernakulam, that is, my district registering the highest active cases at 10,450.

The State Government of Kerala has totally failed in managing the pandemic. They have actually spent more time in managing PR of the Government. But the cases were not attended properly. For a State that constitutes only 3 per cent of India's population, Kerala is contributing to more than one-fourth of the total cases added in the country over the past week. Compared to the national positivity rate that is hovering between 5 and 6 per cent, Kerala is seeing a positively rate of about 12.4 per cent in the recent days.

It is told by the State Government of Kerala that COVID-19 is treated free of cost in the State of Kerala. But it has been a huge financial impact on the underprivileged and the common section of people across Kerala because the ani-viral injection has been charged heavily for this medicine. Also, the Kerala Arogya Suraksha Paditi (KASP) scheme was introduced by the Kerala Health Department. But it should be extended to all the private hospitals so that more and more patients get the benefit of KASP.

Also, the vaccination process, which is going at a very slow pace, has to be taken on a serious note. Vaccination has to happen at different levels which would definitely help the process. I would like to urge the Central Government to send a special team to take care of the COVID-19 situation, especially in my district Ernakulam.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय सभापति जी, महाराष्ट्र- कर्नाटक बॉर्डर अंतर्राज्यीय विवाद लंबे समय से लटका हुआ है। महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के साथ 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा किया है जिसमें बेलगावी, उत्तर कन्नड़, बीदर, और गुलबर्गा और बेलगावी, कारवार, और निप्पनी के शहरों में 814 गाँव शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र मुख्य रूप से मराठी भाषी हैं और महाराष्ट्र चाहता है कि उनका राज्य के साथ विलय कर दिया जाए। विवाद की उत्पत्ति 1956 में भाषाई और प्रशासनिक कारणों के साथ राज्यों के पुनर्गठन में निहित है। पूर्ववर्ती

बॉम्बे प्रेसीडेंसी के एक बहुभाषी प्रांत, जिसमें वर्तमान कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले शामिल थे। 1948 में बेलगाम नगरपालिका ने अनुरोध किया कि मुख्यतः मराठी भाषी आबादी वाले जिले को प्रस्तावित महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया जाए। हालांकि, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने बेलगाम और बॉम्बे राज्य के 10 ताल्लुकों को तत्कालीन मैसूर राज्य (जिसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था) का एक हिस्सा बना दिया। सीमाओं का सीमांकन करते हुए, राज्य आयोग के पुनर्गठन ने मैसूर में 50 प्रतिशत से अधिक कन्नड़ भाषी आबादी वाले ताल्लुकों को शामिल करने की मांग की। अभी यह मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 17 मार्च 2020 को सुनवाई होनी थी जिसकी कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई की तारीख कोविड-19 के वैश्विक विवाद के कम होने के बाद ही तय की जाएगी। विभिन्न कारणों के कारण, 23 जनवरी 2017 के बाद सुनवाई नहीं की जा सकी।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय विवाद पर फैसला नहीं देता, तब तक इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के माननीय मुख्य मंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी की है।

(1605/MK/SAN)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति महोदया, मैं एक अत्यंत ही हृदय विदारक और गंभीर समस्या की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सबको पता है कि पिछले दिनों उत्तराखंड के चमोली जिला में ऋषि गंगा और धौली गंगा के पास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। 14 किलो मीटर रेंज का ग्लेशियर अचानक पिघला और बहुत बड़ी विपत्ति और विपदा आ गई। माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी तत्परता और ताकत के साथ वहां के लोगों को रिलीफ देने के लिए और जो 200 से अधिक लोग लापता हैं, उनको निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में पालिगंज विधान सभा क्षेत्र का एक ग्रामीण नौजवान लड़का, जो एनटीपीसी का काम चल रहा है, उसमें वह कार्यरत था और अचानक इस घटना में वह भी लापता हो गया। दु:खद स्थिति यह है कि उसकी शादी अभी दो महीने पहले हुई थी। उसक पूरा परिवार बिलख रहा है। उसकी बूढी मां, उसकी पत्नी, उसके परिवार के चार-पांच लोग चमोली गए हुए हैं। मगर, अभी तक उसका पता नहीं चल पाया है। इस संदर्भ में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था। पूरी ताकत से उस पर कार्रवाई हो रही है। मुझे विश्वास है कि उसका पता चल जाएगा। सिर्फ पटना के ही नहीं, बिहार के कई लोग लापता हैं। लोग मर्माहत हैं। मैं कल गृह मंत्री जी से भी मिला था और आग्रह किया था कि उस लापता अभियंता, जिसका नाम मनीष है, का पता लगाया जाए। हमारे क्षेत्र के चेसी गांव में ही उसका ससुराल है, लड़का-लड़की दोनों मेरे क्षेत्र के ही हैं। पूरा परिवार बिलख रहा है। वे कल से हमारे यहां बैठे हुए हैं। सैंकड़ों चाहने वाले लोगों ने मुझे फोन किया है। उनके साथ और भी कई लोग होंगे, मेरे ख्याल से सबकी जानें चली गई होंगी। मैं चाहूंगा कि सरकार अविलंब उनका पता लगाकर उनका शव उनके

परिवार को हैंड ओवर कराने की कृपा करें। उस परिवार को कम से कम 25 से 50 लाख रुपये की राशि मुहैया कराई जाए। अभी उसकी पत्नी के हाथ के रंग भी फीके नहीं हुए हैं। उस बच्ची के लिए नौकरी की व्यवस्था हो जाए, तो मैं समझता हूं कि बड़ी कृपा होगी। मुझे पूरा भरोसा है और हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, पूरी ताकत के साथ मनीष को पता लगाने का काम किया जाए और उसके परिवार को हर संभव मदद दिया जाए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का आज मौका दिया है। मैं सोचती हूं कि जब मैं अपनी बात रख दूंगी, उसके बाद आप भी मुझसे सहमत होंगी। काफी सारे सांसद मेरे बोलने से पहले एशोसिएट करने की तैयारी में हैं।

मैं समझती हूं कि पिछले साल सरकार की प्राथमिकता कोरोना से जूझने में अपना योगदान देने की रही है। इसके चलते सांसदों का जो स्थानीय विकास निधि है, उसका पूरा वर्गीकरण कोरोना से जूझने के लिए अगले साल तक के लिए कर दिया गया है। लेकिन, लोग जिस उम्मीद से, जिस भरोसे से हमको चुनकर भेजते हैं, तो वे हमसे कुछ उम्मीदें भी रखते हैं। फिलहाल, महाराष्ट्र राज्य में जो सरकार है, हम महाराष्ट्र के सांसदों की तो इतनी दुर्गती हो गई है कि हमारे कार्यकाल में जो कार्य मंजूर हुए थे, वर्तमान सरकार उसी को रद्द करती जा रही है। हमें जनता के सामने जाना पड़ता है। हम विकास का काम लेकर नहीं जा पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे। यदि सरकार 100 फीसदी नहीं, तो कम से कम कुछ हद तक हमारे स्थानीय विकास निधि को यूज करने की सहूलियत देगी, तो हम भी कुछ काम लेकर जनता के सामने जा पाएंगे। क्योंकि, इससे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ही काम होगा। मुझे लगता है कि आज यहां मौजूद सारे सांसद मुझसे रिलेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि फिर से जनता के सामने जाकर उनके मुद्दे उठाने के लिए और चुनाव के समय उनके सामने वोट की अपील करने के लिए हमारे पास कोई तो चेहरा हो। कोरोना में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन, हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी निधि से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहती हूं कि सांसदों को अपने स्थानीय विकास निधि को खर्च करने की सहूलियत भारत सरकार जरूर दे। धन्यवाद।

(1610/SJN/SNT)

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : सभापति महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग वर्ष 2016 में प्रिंसिपली अप्रूव्ड हुआ था। सिरसा हरियाणा के अंदर एनएच 9 के ऊपर है और चुरू एनएच 52 के ऊपर है। यह 173 किलोमीटर का नेशनल हाइवे वर्ष 2016 में प्रिंसिपली अप्रूव्ड हुआ था। इसके बाद इसका डीपीआर का काम दिया गया था। आज डीपीआर के काम को पूरे हुए दो साल से ज्यादा का समय हो गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हाइवे है। इस रोड की ऐसी हालत है। हालांकि आज की तारीख में यह स्टेट

हाइवे के रूप में है। जब से प्रिंसिपली अप्रूवल हुआ है, तब से स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तारानगर से चुरू 35 किलोमीटर की रोड के ऊपर कम से कम ढाई घंटे का समय लगता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर चुरू होने के कारण वहां बहुत-सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रिंसिपली अप्रूव्ड हैं और दो-दो सालों से जिनका डीपीआर बन चुका है, उन राष्ट्रीय राजमार्गों को नंबर दिया जाए। नंबर देने के पश्चात् बजट का आवंटन किया जाए, ताकि वह रोड बन सके। वह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। डायरेक्ट पंजाब से गुजरात को जोड़ने के लिए वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाइवे है। हमने बहुत मेहनत और कोशिश करके उसको अप्रूव्ड करवाया था। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि सरकार इसके लिए बजट का आवंटन करे।

*DR. BHARATI PRAVIN PAWAR (DINDORI): Hon. Madam Chairperson, thank you very much. Today, I am going to raise a very important issue. Whether it is Corona pandemic or any natural calamity, our farmers remain the backbone and driving force of our economy.

In my constituency Nashik, farming related works for the crops like grapes, wheat, onion, gram and other rabi crops are going on and watering of the crops during these days is very important. But a GR has been issued by Government of Maharashtra regarding paying of electricity bills. They are going to stop electricity supply if you fail to pay the pending electricity bills. Electricity department is disconnecting the supply of electricity even in such villages even though most of the farmers have paid their bills and only a few farmers are unable to pay.

I condemn this decision of Maharashtra Government and through you, I demand to restore the supply of electricity to the poor and needy farmers in my constituency.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Chairperson.

Madam, you are really aware of the five State Assembly elections which will be held very soon. The Election Commission is going to announce the dates in this month or in the beginning of the next month. The Government of Kerala has been regularizing lakhs of temporary and contractual employees without following reservation policy. Thousands of Scheduled Castes and Scheduled

* Original in Marathi.

Tribes, educated unemployed youth are being denied their employment opportunities in Kerala.

Madam, you are very much aware of the fact that Scheduled Castes and Scheduled Tribes educated unemployed youth get employment only through Public Service Commission or Employment Exchange. In private sector, there is not any reservation. Only in the Government sector, the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe youth will get reservation. Elections are very near in Kerala. The Government of Kerala is bypassing Public Service Commission and the Employment Exchange.

Madam, you are aware that Public Service Commission is a constitutional body. But the State Government is politicalizing the Public Service Commission, and backdoor appointments are going on. Ultimately, Madam, our poor unemployed youth of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not getting chance either in Government service nor in private sector.

(1615/RBN/YSH)

This is a very serious situation. So, I would like to request the hon. Central Government, through you, to intervene in this matter and ask the State Government to stop this back door appointment. This is back door appointment because *… (Not recorded)* of the leaders, MLAs, MPs, ex-MPs and Ministers of the *… (Not recorded)* are being given permanent employment.

Therefore, I would like to request the Government of India to intervene in this matter and stop the back door recruitment in Kerala Government service. Thank you.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): सभापति महोदया, धन्यवाद। आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए विषय पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना, मेरे संसदीय क्षेत्र की अतिमहत्वपूर्ण और बहुत पुरानी परियोजना है। इस परियोजना की वर्ष 2014 से पहले की स्थिति यह थी कि इसका सारा काम ठप्प पड़ा हुआ था। इस परियोजना को सरकार के माध्यम से कुछ भी धनराशि नहीं मिल रही थी।

सभापति महोदया, मैं केन्द्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि इस परियोजना को वर्ष 2014 से अब तक लगातार धनराशि आबंटित की जा रही है। उसके माध्यम से यह परियोजना अपनी गति को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है।

सभापति महोदया, इस परियोजना में एक छोटी सी अड़चन आती है। यह अड़चन रोजगार से जुड़ी हुई है। इस परियोजना में हमारे सभी अभ्यर्थियों का भूमि अधिग्रहण हो गया है और जिनका भूअधिग्रहण हुआ है और उससे रोजगार का जो विषय जुड़ा हुआ है, वह अब लंबित पड़ा है। मेरे

आग्रह पर रेलवे का दिनांक 11.11.2019 का जो आदेश था, उसमें यह था कि जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, उनके अधिग्रहण के बाद उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। इसी आशा से मैंने पहले भी इस विषय को आपके माध्यम से सदन में रेल मंत्री जी के सामने रखने का प्रयास किया था। उस आदेश में यह था कि उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि हमारे मण्डल के जो अधिकारी हैं, उस मंडल के माध्यम से लगातार यह कहा जाता है कि इस आदेश के विपरीत दिनांक 11.11.2019 के बाद आपके जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार हम आपको रोजगार उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारे यहाँ के सभी अभ्यर्थी, जिन्हें रोजगार मिल चुका है और जो इस प्रक्रिया में शामिल हैं, वे आशान्वित हैं कि आने वाले समय में उन्हें भूअधिग्रहण के इस विषय से रोजगार मिलेगा। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि रेल मंत्री जी के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की विशेष कृपा की जाए।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): मेरा सबसे आग्रह है कि आप एक-एक मिनट में अपनी बात खत्म करें। काफी माननीय सदस्य बचे हुए हैं। हमें पाँच बजे तक हाउस को उठाना है, इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि एक मिनट से अधिक समय कोई न ले।

श्रीमती रंजीता कोली (भरतपुर): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। आपने मुझे सदन में बोलने के लिए मौका दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र भरतपुर की तरफ दिलाना चाहूँगी। मेरा संसदीय क्षेत्र भरतपुर वर्ष 2013 में एनसीआर में शामिल कर लिया गया था। मुझे बड़ा दुख है कि मेरे द्वारा कई बार बोलने के बाद और पत्र-व्यवहार करने के बावजूद भी आज तक हमें एनसीआर में शामिल होने का लाभ नहीं मिला है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि एनसीआर की जो भी सुविधाएं हैं, वे भरतपुर जिले को मिले, जिससे भरतपुर जिले में भी विकास की गंगा बह सके।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (कोडरमा): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपका ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र की तरफ आकृषित करना चाहती हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि ट्रेन आम जन-जीवन की लाइफ लाइन है और आवागमन सुलभ हो सके, इसके लिए रेल मंत्रालय भी प्रतिबद्ध है। कोविड-19 की गाइडलाइन की वजह से अनेक ट्रेनों का ठहराव सभी स्टेशनों पर नहीं हो रहा है।

(1620/RPS/SRG)

मैडम, आपने मुझे समय कम दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं, मैं अपने आपको खुशनसीब समझती हूं कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आती हूं, वहां रेलवे और हाइवे, दोनों की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन आज लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि वहां रेल का ठहराव नहीं हो रहा है।

गया से धनबाद तक जो पैसेंजर ट्रेन चलती थी, अभी वह बन्द है। वाराणसी से आसनसोल तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन भी बन्द है। इसकी वजह से दैनिक कर्मियों को रोज आने-जाने में काफी परेशानी होती है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगी कि उन ट्रेन्स का परिचालन जल्द से जल्द शुरू

हो। कई ऐसी ट्रेन्स हैं, जिनका ठहराव कोडरमा स्टेशन, चौधरी बांध, सरमाटांड़, परसाबाद में होना है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि सियालदह राजधानी एक्सप्रेस (12313 और 12314) का कोडरमा में ठहराव किया जाए। इसी तरह 12321 और 12322 का चौधरी बांध स्टेशन पर ठहराव किया जाए। परसाबाद स्टेशन पर 12801 और 12802 ट्रेन्स का ठहराव हो, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। इसके साथ ही साथ, चूंकि हम चार धाम यात्रा की भी सुविधा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह बाबा धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला लगता है। इसलिए कोडरमा से देवघर और देवघर से लेकर तारापीठ, जो वेस्ट बंगाल में रामपुर हाट में है, तक एक नई ट्रेन की शुरूआत की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): धन्यवाद, सभापति महोदया।

सभापति महोदया, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से आता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में श्रीगंगानगर के अलावा हनुमानगढ़ जिला भी है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है। मेरे संसदीय क्षेत्र में आने वाले हनुमानगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन पर सोलर ऊर्जा पैनल स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। यह जिला मुख्यालय एक रेलवे हब के रूप में विकसित हो सकता है। यहां से बहुत सी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं और यहां से बठिंडा की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। यहां पर वाशिंग लाइन है और पर्याप्त जगह है।

सभापति महोदया, हनुमानगढ़ में रेलवे की करीब 300 एकड़ भूमि है, जिस पर कब्जा हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वाशिंग लाइन के लिए 300 एकड़ भूमि पर्याप्त है, इसलिए वहां पर एक वाशिंग लाइन लगाई जाए। वहां सोलर पैनल स्थापित करने से सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा और यह रेलवे स्टेशन एक ग्रीन रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित हो जाएगा।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कोरोना काल में मेरे संसदीय क्षेत्र में जितनी ट्रेन्स बन्द हुई हैं, उनमें से काफी ट्रेन्स चालू हो गई हैं और काफी ट्रेन्स आज भी बन्द पड़ी हैं। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि वे सारी ट्रेन्स पुन: बहाल की जाएं, ताकि रेल यात्रियों, मजदूरों, किसान वर्ग और सेना के जवानों, आदि सभी यह को सुविधा मिल सके, क्योंकि हम लोग बॉर्डर पर रहते हैं और वहां पर सेना का काफी आना-जाना होता है। धन्यवाद।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Madam, in 2010, a Kendriya Vidyalaya was sanctioned in Subarnapur district within my Parliamentary constituency. For the last 11 years, it has been functioning out of temporary premises, even though it has a student strength of over 5000. Now, in January 2019, the foundation stone for the Kendriya Vidyalaya building was laid by none other than our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, and in September, 2019 Rs. 4,70,00,000 were sanctioned for the construction of this building. However, the total estimate for the construction of the Kendriya Vidyalaya is Rs. 15,03,00,000. Madam, through you, I would like to request the

hon. Minister of HRD, I am lucky he is sitting here, to release this balance money as early as possible as the Parent-Teacher Body has approached me since the children are suffering undue inconvenience. There is no playing field. I would request hon. Minister to look into the issue urgently.

(1625/SPS/AK)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) : सबसे आग्रह है कि हमको पांच बजे उठना है, सिर्फ एक मिनट में अपनी बात कहिए।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर) : सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं, जिसकी सिफारिश वर्ष 2015 में हमारी संसदीय समिति द्वारा भी की जा चुकी है। हालांकि, सरकार की विशेषज्ञ समिति ने इसे 12 लाख रुपये करने की सलाह दी है, लेकिन सरकार से आग्रह है कि इसे टुकड़ों-टुकड़ों में न बढ़ाकर, 6 से 8 लाख, 8 से 12 लाख और 12 से 15 लाख रुपये न करके, सीधे 15 लाख रुपये किया जाए।

इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि सरकारी नौकरियों में जो गेजेटेड दर्जा प्राप्त परिवार हैं, उनको भी ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया जाए, क्योंकि सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, जो हमारी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, उसको चलाने के बावजूद भी, ओबीसी के कोटे की वैकेंसीज का बैकलॉग अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि ओबीसी क्रीमीलेयर की आय सीमा को 15 लाख रुपये बढ़ाते हुए, गेजेटेड दर्जा प्राप्त परिवारों को भी ओबीसी आरक्षण का लाभ दिए जाने के लिए निर्णय लें।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): सभापति महोदया, धन्यवाद, आपने मुझे शून्य काल में मेरे लोक सभा क्षेत्र आगरा के कुछ विषय उठाने का मौका दिया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में पर्यटन के दृष्टिकोण से भारत 65 से 35 वें नंबर पर आ गया है। हम 5 वें नम्बर पर आ सकते हैं, अगर जो बातें मैं कह रहा हूं, वे बातें मान ली जाएं। अगर उचित कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के मापदण्डों को देखते हुए, अगर ताजमहल को रात में 11 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इसी प्रकार से अगर आगरा में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाए तो वहां लोग दो दृष्टियों से आएंगे, एक तो मैच देख लेंगे और दूसरा ताजमहल भी देख लेंगे। इससे विदेशी दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। इसी प्रकार से यमुना नदी पर बैराज, बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरता हुआ भू जल स्तर बहुत संकट पैदा कर रहा है। आगरा उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा वाहिद जिला है, जिसके 99 परसेंट ब्लॉक प्रॉब्लमैटिक हो गए हैं, जिनको हम डार्क ब्लॉक कहते हैं। अगर बैराज बन जाएगा तो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, पेयजल संकट दूर हो जाएगा और गिरता हुआ भू जल स्तर ऊपर हो जाएगा। इसी के साथ-साथ ताजमहल की बुनियाद लकड़ी पर है। विशेषज्ञ कहते हैं कि उसको नमी की जरूरत है तो उसके लिए पानी हो जाएगा। वहां वाटर स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। हर शहर, जिसमें नदी है, वहां रिवर फ्रंट ने ही पर्यटन को बढ़ाया है। जैसे, साबरमती अहमदाबाद में है,

टेम्स, लंदन में है या गोमती, लखनऊ में है। मेरी एक मांग यह है। दूसरा, सैनिक स्कूल के लिए कहा गया है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : बघेल जी, एक ही विषय रखिए, बाकी अगली बार रखिएगा। अब आप बैठिए।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : जीरो ऑवर में दो विषय नहीं आते हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। आपने बैराज का आग्रह कर दिया है, बाकी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

…(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एंव पूर्वी चम्पारण जिले की जर्जर सड़कों की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं, जिसके कारण लोगों को आवागमन में विशेषकर बरसात के समय में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बिहार में आई बाढ़ के कारण उक्त तीनों जिलों की कई ग्रामीण सड़कें एंव पुल-पुलिया ध्वस्त हो चुके है, जिनकी मरम्मत, सडकों का समुचित रख-रखाव एवं पुनर्निर्माण जनहित में अति आवश्यक है। मेरे क्षेत्र में निर्मित ऐसी सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनकी अनुरक्षण की अवधि पांच वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनकी मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य सरकार को करना जरूरी है, क्योंकि अनुरक्षण की अवधि समाप्त होने पर विभाग निधि के अभाव में इन सडकों पर कोई कार्य नही करते हैं। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सडकें एंव अन्य ग्रामीण सड़कें तथा पुल-पुलिया ध्वस्त होने के कारण लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। आम जनजीवन एवं विकास कार्यो पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि जनहित में मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एंव पूर्वी चम्पारण जिले की जर्जर ग्रामीण सड़कों एंव पुलों को चिह्नित करते हुये, उनकी मरम्मत एंव निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

DR. R.K. RANJAN (INNER MANIPUR): Madam, thank you very much for giving me this opportunity.

It is my privilege to raise this issue in this august House expressing the aspiration of Netaji admirers and INA families to organize the concluding ceremony of *Parakram Diwas* in Manipur where the actual INA campaigns took place on the Indian soil.

(1630/SPR/RAJ)

A high-level committee, organising a year-long celebration of the 125th Birth Anniversary of Netaji, is a welcome step in the right direction in the national interest.

Madam, Manipuris are very proud to be a part of the freedom struggle as they are directly linked with the INKA campaigns. It was at Moirang, Manipur, the Indian tri-colour flag was first hoisted on April 14, 1944, on the Indian mainland. Although, Andaman was the first. The first INA office on the Indian soil was set up at Moirang some 34 km. away from Imphal. This is also one of the places where the INA operated the First Provincial Government of Independent India. From this location, the slogan *Delhi Chalo* was further echoed and reverberated. More than 7,000 INA soldiers waged the Imphal battle.

With this admirable historical background, I, on behalf of the people of Manipur, and the INA associates, would like to seek your kind indulgence for a favourable consideration to the proposal of holding the closing ceremony of Netaji's 125th Birth Anniversary celebration in and around Moirang, Manipur. An amazing show stopper event of *Parakram Diwas* in Manipur would be a fitting tribute to Netaji and INA.

श्री सय्यद इम्तियाज जलील (औरंगाबाद): सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान ऐसे तबके की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी आवाज सदन तक नहीं पहुंचती है। महाराष्ट्र में हमालों को मराठी में माथाड़ी कहते हैं, यानी जो सर पर थैले रख कर, रेलवे वैगन या ट्रकों से उतारते हैं या मार्केट में काम करते हैं, ऐसे लाखों लोग हैं। उन्हें माथाड़ी कहते हैं। उनका शोषण न हो, इस वजह से महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 25 साल पहले माथाड़ी बोर्ड्स बनाए। तकरीबन ऐसे 36 माथाड़ी बोर्ड्स बनाए गए हैं, जो महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में हैं – पुणे, कोंकण, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, अमरावती। इनका मकसद यही था कि कोई इन माथाड़ियों का शोषण न करे, लेकिन यह हो रहा है कि जो मेहनत करते हैं, उनको डायरैक्ट पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि वह पैसा माथाड़ी बोर्ड के पास जाता है। उसका चेयरमैन कोई पॉलिटिकल अप्वाइंटी होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेहनत-मजदूरी माथाड़ी कर रहा है, लेकिन माथाड़ी बोर्ड 30 प्रतिशत पैसा अपने पास रख लेता है और 70 प्रतिशत पैसा उन्हें देता है। अगर पिछले 25 सालों का हिसाब निकाल कर देखें, तो बोर्ड जो 30 प्रतिशत पैसा अपने पास रखता है, उसमें से 12 प्रतिशत कम्पोनैंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए है। कम्पोनैंट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट्स, 1952 के तहत किसी भी संस्था/संगठन में 22 से ज्यादा कर्मचारी हैं, तो उनका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में जमा होना चाहिए। लाखों मजदूरों का पैसा पीएफ के नाम पर जमा किया जा रहा है, लेकिन एक रुपए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में जमा नहीं किया जा रहा है, उसमें नहीं दिया जा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। मैं समझता हू कि अगर सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी तो सभी 36 बोर्ड्स के चेयरमेन जेल के अंदर जाएंगे। लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मजदूरों की देख-रेख करने की होती है, उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं सरकार

से यह अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द जो पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा गया है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएफ एकाउंट में ट्रांसफर किया जाए।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): श्री जगदम्बिका पाल।

कृपया, आप सभी एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आप ने तीन मिनट कहा है।

माननीय सभापति : नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए समय दिया है। मैं वह बात कह रहा हूं, जिससे आप भी संबंधित हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसे वे लोग हैं, जो आपके मतदार हैं, जो आपका समर्थन करते हैं। यह अत्यंत महत्व का विषय है। सदन के समक्ष यह विषय कई बार उठ चुका है। इसके लिए इस सदन की सहमति मिली है और कई सत्र में मंत्रियों की तरफ से भी आश्वासन मिला है। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है, जो दिल्ली के घाटों पर भी सुनने को मिलती है और आपके क्षेत्र से लेकर अन्य कई जगहों पर बोली जाती है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लोकप्रिय मुहावरे का प्रयोग मोदी जी ने किया है। आज यह भाषा मॉरिशस में सेकेंड लैंग्वेज हो गई है, वहां के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, सूरीनाम, ट्रिनिडाड और नेपाल में पढ़ाई जा रही है, दुनिया के 25 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

(1635/VB/UB)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): श्री जगदम्बिका जी, अब भूमिका बनाना बंद कीजिए और अपनी बात कहिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सदन में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर बैठे हैं और अभी गृह मंत्री जी यहाँ से गए हैं, इसमें कोई परिव्यय नहीं है, कोई व्यय नहीं है। लेकिन करोड़ों लोगों की भावनाएँ इससे जुड़ी हैं, यह हमारी मातृभाषा है। निश्चित रूप से यह भाषा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका महत्व कई देशों में है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): My Constituency of North Chennai is a highly industrialised area. Though it has brought advantages of employment, there are disadvantages also where there is a huge amount of pollution of water, air and soil.

With this backdrop, I would like to bring to the attention of the Government that there is a port in Kattupalli owned by Adani. It is called 'Kattupalli Adani Port' (MIDPL Port). There is a proposal for expansion of this Port to three times of the existing size. I would like to bring to the notice of this House that this is illegal on three accounts. First, it is in violation of the Coastal Regulation Zone Notification

where they have notified that the areas which have high erosion should not be taken up for any import activity. The erosion in this area has already been documented to be about 15 metres per year.

The second point is that there is a prohibition of conversion of wetland to industrial land. Here, in this proposal, they are having about 6000 hectares of land which is going to be taken up for this project out of which, one third is private, one third is public and one third is a reclaimed land of the sea. The amount of reclamation of the land is going to be used where it is going to affect the people of the local districts.

The third point is that, according to the Environmental Impact Assessment Act, it says that eco-sensitive areas should not be affected and there is a Pulicat Lake over there. The fishermen and farmers of these areas would be affected. There are water bodies which will be taken up for this project which will also cause flooding and water scarcity. I would like to request the Government to ensure that this project is dropped.

श्री सुनील सोरेन (दुमका): माननीय सभापति महोदया, झारखण्ड राज्य में वर्ष 2019 में तीन नए मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना की गई थी, इनमें से एक हमारे संसदीय क्षेत्र दुमका में स्थापित फुलो-झानों मेडिकल कॉलेज भी है। इन तीनों मेडिकल कॉलेजेज में से दुमका मेडिकल कॉलेज की स्थिति अति दयनीय है। यहाँ लैब, कैडेवर एवं रसायन की सुविधा का अभाव है। इसके साथ-साथ यहाँ लैब असिस्टेंट और पैरा-मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। इतना ही नहीं, यहाँ पुस्तकालय एवं पुस्तकालय कर्मियों की भी कमी है।

कॉलेज में चिकित्सा-शिक्षक की कमी के कारण चिकित्सकों का घोर अभाव है। यहाँ बिजली-पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित एक राष्ट्रीय टीम निरीक्षण हेतु दुमका मेडिकल कॉलेज गई थी। दुमका मेडिकल कॉलेज की संरचना राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदण्ड के अनुसार नहीं होने के कारण नए सत्र में छात्र-छात्राओं का नामांकन बन्द कर दिया गया है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मापदण्ड के अनुरूप उपरोक्त वर्णित गंभीर समस्याओं का निदान अतिशीघ्र किया जाए ताकि छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन व्यवस्थित ढंग से हो सके और छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Madam Chairperson, there is a long pending request for setting up of a government medical college in Raigarh which is an aspirational district. I met Dr. Harsh Vardhan also and he promised that once the DPR is sent from the State Government, he would expedite the

approvals. There have been a lot of agitations from different civil societies, Press Union, the Congress Party, many other people, and we have had rallies and so on, but the State Government has turned a deaf ear to the valid request of the tribal people in Raigarh District. A similar protest has been happening in Kendrapara District and Bhadrak District also. I would request through you, Madam, the hon. Health Minister, Dr. Harsh Vardhan ji, to write to the State Government and seek the reason as to why the DPR was not sent so far and why the State Government is not looking after the development or setting up of a government medical college in an aspirational district like Raigarh.

(1640/PC/KMR)

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): माननीय सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र बिहार का महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र है। वह सारन जिले की चार असेंबली कांस्टिुएंसी और सीवान जिले की दो असेंबली कांस्टिुएंसी मिलाकर बना है। वहां दो केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से एक केन्द्रीय विद्यालय मशरख में है। वहां केन्द्रीय विद्यालय का भवन बन गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस विद्यालय को दो पाली में, दो शिफ्ट में चलाने की अनुमति दें। जो केन्द्रीय विद्यालय महाराजगंज में है, वह भवन विहीन है, बच्चों के बैठने की स्थिति नहीं है, उन्हें काफी परेशानी होती है, बरसात के दिनों में भी काफी दिक्कत होती है।

अत: वहां भवन बनाने की अनुमति दी जाए। मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं कि आप नई शिक्षा नीति लाकर अलग-अलग तरीके से, पूरे देश में शिक्षा की ज्योति जलाने का कार्य कर रहे हैं, चाहे वह टैक्निकल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं आग्रह करूंगा कि मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, इसलिए वे इस पर अपने स्तर से कुछ आश्वस्त कर दें कि आगे आने वाले दिनों में इस कार्य को वे देखेंगे। धन्यवाद।

SHRI B. B. PATIL (ZAHIRABAD): Madam Chairperson, I would like to bring to the kind notice of hon. Minister of Health and Family Welfare various concerns of Bidi Manufacturers Association of our Telangana State and across other parts of our country.

Bidi industry is a cottage industry and provides employment to over 85 lakh bidi workers. Most of them are in rural areas and that too women. Moreover, the Bidi manufacturing factories do not contribute to any pollution nor do they require power and machinery. But sadly, the industry is not getting any support or incentives from the Government.

Now the Ministry of Health & Family welfare, Government of India, proposes to amend COPTA 2003. Most of the proposed amendments are

directly going to affect sale of bidis drastically. This in turn will affect production of bidis drastically. As a result, livelihood of over 2.60 crore tobacco farmers and farm workers; over 85 lakh bidi workers; over 40 lakh tribals engaged in plucking tendu leaves; and over 72 lakh traders, retailers/panwalas will be affected.

The proposed increase in fines for offences will open flood gates of corruption across the country. I, therefore request the hon. Minister to withdraw the proposed amendments in the interest of livelihood of 4.57 crore people dependent on tobacco industry.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदया, धन्यवाद।

महोदया, कोरोना महामारी के कारण ट्रेन्स बंद हो गई थीं। वे ट्रेन्स अब वापस धीरे-धीरे शुरू की जा रही हैं, लेकिन उनके स्टॉपेज कम कर दिए गए हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में, जिस ट्रेन से मैं पिछले छ: सालों से बराबर आ रहा था, वह मेवाड़ एक्सप्रेस थी। वह निज़ामुउद्दीन से उदयपुर के लिए चलती है। वह मेरे लोक सभा क्षेत्र में मंडलगढ़ स्टेशन पर रुकती थी। अब चूंकि उस ट्रेन का वहां रुकना बंद हो गया है, इसलिए मेरा उस ट्रेन से आना भी बंद हो गया है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जो ट्रेन्स लॉकडाउन की वजह से बंद की गई थीं, वे अब शुरू हो रही हैं। इसलिए, उन ट्रेन्स के जो पहले स्टॉपेज थे, वे स्टॉपेज ही मेंटेन रखे जाएं, ताकि आगे आने वाले समय में लोगों को कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): माननीय सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

महोदया, मैं अपने जिले जौनपुर में बजाज कंपनी द्वारा बिजली की सप्लाई आपूर्ति किए जा रहे सौभाग्य योजना के दुर्भाग्य के बारे में आपके समक्ष एक-दो बातें रखना चाहता हूं।

इस योजना के तहत 60 हजार एनर्जी मीटर्स लगाए गए हैं, जिनमें से 40 हजार मीटर्स तो बिलकुल ही चार्ज नहीं किए गए हैं। कागजों में बहुत गांवों को संपूर्ण दिखाया गया है, जबकि हकीकत में वहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इससे जनता में बहुत आक्रोश है।

(1645/IND/GM)

जौनपुर के लगभग 760 गांव ऐसे हैं, जिनमें खंभे लगा दिए गए हैं।...(व्यवधान) आप टोका-टाकी मत कीजिए। मैं जो बयान दे रहा हूं वह सही है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): श्याम सिंह जी, आप सिर्फ प्वाइंटेड बात कीजिए।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

माननीय सभापति : गलत सही की कोई बात नहीं है। आप सिर्फ प्वाइंटेड बात कीजिए। आपके पास एक मिनट का समय है। केंद्र सरकार से जो डिमांड करनी है, वह कहिए।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदया, हम यहां प्रदेश की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यहां प्रदेश की बात नहीं कर सकते हैं। आप केंद्र सरकार से जो चाहते हैं, वह बताइए।

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदया, जब हम गांव का दौरा करते हैं, तब जो दलित हैं, गरीब हैं और जो पिछड़े हैं, जिनकी बस्तियां हैं, जहां पोल लगाया गया है लेकिन वहां तार भी नहीं हैं। मीटर भी नहीं है, उनको भी बिजली विभाग गलत बिल भेज देता है और हजारों रुपया वसूल करता है। मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस समस्या का हल होना चाहिए।

मेरा दूसरा बिंदु है कि दिन में अठारह घंटे बिजली सप्लाई होती है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : दूसरी बात नहीं रख सकते हैं। आप बैठ जाएं।

श्री विनोद कुमार सोनकर जी।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): सभापति महोदया, मैं कौशाम्बी लोक सभा से निर्वाचित हो कर दोबारा आया हूं। कौशाम्बी लोक सभा में दो जनपद प्रतापगढ़ और कौशाम्बी हैं। कौशाम्बी 4 अप्रैल, 1997 को जिला बना, जिसके कारण सारे शैक्षणिक संस्थान चाहे इंजीनियरिंग कालेज हों, मेडिकल कालेज हों या डिग्री कालेज हों सब के सब प्रयाग जिले में चले गए। कौशाम्बी जनपद के पौराणिक महत्व को देखते हुए उसे जिला बनाया गया। जब यह नया जिला बना, तो यहां केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आरक्षित की गई। मैं पिछले छह साल से माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि वहां एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाए, जिसके लिए आपके विभाग द्वारा जमीन का सर्वे भी किया गया। जब जमीन को रिजेक्ट किया गया, तो दूसरी जमीन दी गई और विद्यालय को अस्थायी चलाने के लिए एक जगह का सर्वे किया गया। माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आज इस विषय में कुछ भाषण दें। पिछले साढ़े छह साल से मैं लगभग छह-सात बार इस विषय को उठा चुका हूं और कौशाम्बी लोक सभा में 20 लाख से ज्यादा लोग हैं, जिनके पास शैक्षिक व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जमीन भी दे दी गई है और अस्थायी परिसर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। वहां केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दें। आज सौभाग्य से मंत्री जी सदन में हैं। यदि वे कोई आश्वासन दे दें, तो बेहतर होगा।

श्री संजय सेठ (राँची): महोदया, झारखंड में रांची के अंदर एक भारी उद्योग एचईसी है। उसमें कामगारों का एरियर बकाया है। ऐसे 7300 कामगार हैं, जिनका 1997 से लेकर 2008 तक का बकाया है। उनमें से बहुत से बूढ़े हो गए हैं और कितनों का देहांत हो चुका है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है। मेरा भारी उद्योग मंत्रालय से अनुरोध है कि उनका एरियर चुकता कराएं। पहले जब बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिटी परियोजना में यदि जगह बिकेगी, उस पैसे से एरियर के बकाया को वसूल कर लिया जाएगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसे जो 7300 करीगर हैं, वे रांची की रीढ़ हैं और यह उनके पसीने की कमाई है। उनके एरियर के पैसे का जल्द भुगतान किया जाए।

श्री राजकुमार चाहर (फतेहपुर सीकरी): महोदया, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में, जो आगरा जनपद का पूरा देहात का क्षेत्र है, राजस्थान के बार्डर के साथ लगे हुए गांव के बारे में बताना चाहता हूं, जहां पानी की बहुत किल्लत है। वहां जल स्तर 400 मीटर तक नीचे चला गया है और सिंचाई की बहुत दिक्कत है। लगभग 10 हजार हेक्टेयर किसानों की भूमि बंजर हो गई है। पहले वहां खारा पानी हुआ करता था, अब वह भी नहीं है। अकबर के जमाने से लेकर अब तक वहां पानी की समस्या चलती आ रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी

ब्लॉक में एक नहर की व्यवस्था की जाए, जिससे हजारों किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सके। इससे उनकी बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और वह खुशहाल होगा।

माननीय सभापति : समय बहुत कम है, इसलिए सभी प्वाइंटेड बात कीजिए।

*SHRI Y. DEVERDRAPPA (BELLARY) : Hon'ble Chairperson, Madam thank you very much for allowing me to raise an issue pertaining to fix the Maximum Retail Price for farm machineries.

My Lok Sabha constituency Bellary is in Karnataka state. Our farmers all over the country are largely dependent on farm machinaries, without which it is very difficult to take up agriculture now a-days. Therefore I would like to request the government to take steps to fix the MRPs of farm machinaries and publicize it in the websites of both the government departments and the manufacturing companies. I also request the union government to bring such a law in the next session of Parliament. So that interest of our farmers in the country would be protected. Considering the present phenomenon of the agriculture sector of the country, it is impossible to take up farming without machineries. Therefore the government should issue directions to the manufacturing companies of agriculture equipments to display all the prices of the farm machineries in the companies' own websites. And the price of each machinery along with the maintenance charges should be displayed in the respective equipments such as tractor, power tiller, combined harvesters, rotovators and paddy planters, sugarcane cutting machineries etc, in the showrooms for the benefit of farmers.

I humbly submit to all the hon'ble members of the House to support this issue and urge the government to do needful in this regard to help the farming community of the country.Thank you.

(1650/KDS/RCP)

श्री कृष्णपालसिंह यादव (गुना): धन्यवाद सभापति महोदया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर तांत्या टोपे जैसे महान योद्धा की बलिदान स्थली, मेरे गुना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवपुरी में स्थित है। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई जी के साथ मिलकर अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला किया था। राज्य सरकार और कुछ सामाजिक संस्थाएं इस पवित्र स्थल को संवारने के लिए काम करती आ रही हैं। आपके माध्यम से मेरा माननीय पर्यटन मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वीर तांत्या टोपे जैसे महान योद्धा की इस बलिदान स्थली को केंद्र सरकार द्वारा

* Original in Kannada

विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाते हुए केंद्रीय संग्रहालय अनुदान योजना के अंतर्गत यहां एक मेमोरियल संग्रहालय व थियेटर की स्थापना की जाए, जिससे कि यह पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षण का केंद्र बने और वहां के लोक कलाकारों द्वारा लोक कलाएं प्रस्तुत करने व अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके। मैं इसके साथ ही केंद्र सरकार व माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शिवपुरी व चंदेरी के पर्यटन के विकास के लिए इस बजट में फंड एलोकेट किया है। धन्यवाद।

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): धन्यवाद सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र एवं जिला राजनंदगांव के वनांचल एवं आदिवासी बहुत नक्सल प्रभावित मानपुर मोहला, चौकी में नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बेतहाशा अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन खतरे में आ चुका है। अवैध रेत खनन की स्थिति यह है कि विकास खंड मानपुर के ग्राम तोलुम व नवागांव में नदी की दिशा ही बदल गई है। बिना रॉयल्टी पर्ची के शासन को लाखों रुपयों का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। बेशकीमती सागौन सहित इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई कर उनको पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में भेजा जा रहा है। नदी का कटाव बढ़ने और नदी से लगी भूमि व खेतों के क्षरण से आदिवासी कृषकों में आक्रोश की स्थिति पैदा हो रही है, जिसका विरोध वे गत दो वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। यह स्थिति न सिर्फ उक्त स्थान वरन् में है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की यही स्थिति है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पर्यावरण मंत्रालय सहित खनन विभाग व एनजीटी निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में एक आपदा आई हुई है, जिसमें बहुत से लोग लापता हुए हैं और मारे गए हैं। हमारे जिला-सहारनपुर के तकरीबन 25 से ज्यादा लोग लापता हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस वक्त वहां पर जो राहत कार्य हो रहा है, उसमें तेजी लाई जाए और इसके साथ-साथ बचाव दल की संख्या भी बढ़ाई जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट कम से कम 25-25 लाख की सहायता राशि देने का कार्य करें। इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि यह पूरा सदन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है।

श्री संगम लाल गुप्ता (प्रतापगढ़):माननीय सभापति महोदया, मैं प्रतापगढ़ लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में शहर मुख्यालय पर जमीन की उपलब्धता होने के बावजूद भी जिलाधिकारी ने प्रस्ताव भी भेज दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे यहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए, क्योंकि टेम्परारी विद्यालय चलाने के लिए भी बिल्डिंग की उपलब्धता हो चुकी है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे शहर मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए। धन्यवाद।

(1655/CS/RK)

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): महोदया, आपने मुझे मेरे क्षेत्र कुरुक्षेत्र की अति लोक महत्व की बात उठाने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र हमारी एक धार्मिक नगरी है, वहां पर एलीवेटेड रेलवे ट्रैक बनाने की पिछले बजट के अंदर जो बात आई थी, उसका काम चालू हो गया है। मैं उसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसी रेल ट्रैक के ऊपर आगे कैथल में भी एक एलीवेटेड रेलवे ट्रैक का कैथल शहर के अंदर सर्वे हुआ था।

मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि उसका भी जल्दी बजट जारी करके उसके ऊपर भी इसी तरह काम किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिले।

महोदया, उसी रेलवे ट्रैक के ऊपर मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंदर कैथल विधान सभा में डांड गांव पड़ता है। वहां पर एक रेलवे स्टेशन है। उस रेलवे स्टेशन का नाम बेहवा रोड रेलवे स्टेशन रखा हुआ है। वहां के लोगों की मांग है कि उसका नाम बदलकर डांड रेलवे स्टेशन किया जाए। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्राय: हम लोग अपने क्षेत्र की बात यहां पर रखते हैं। मैं आज शिक्षा के क्षेत्र का विषय उठा रहा हूं। मैं भारत की सरकार का, आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी का और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय निशंक जी का आभार प्रकट करता हूं कि शिक्षा नीति में बदलाव के पूरे देशवासियों के जो सुझाव थे, उनको लेकर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास किया है। पूरे देश को इस बात का पता है कि बीच में हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम को ऐसा कोलैप्स किया गया कि लोग याचक बनकर नौकरी ढूंढने का काम करते थे। कोई दाता बनकर या रोजगार देने को लेकर कोई शिक्षा नहीं थी। यहां तक कि अपने पूर्वजों पर गौरव करना भी हम लोग भूल गए थे। हमारे सिलैबस से वह हटा दिया गया था। जैसे अभी प्रधान मंत्री जी ने आंदोलनजीवी लोग नाम लिया, मैं सरकार को इस सदन के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि जैसे किसानों को लेकर एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे ही आने वाले समय में हमारी शिक्षा नीति पर, जो कि सही है, उचित है और देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाली शिक्षा नीति है, उसको ले कर कोई एक कुचक्र चलाया जा रहा है। इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दें और उसका प्रबंध करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी): महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज से 11-12 वर्ष पूर्व चार-चार उड़ानें भुंतर एयरपोर्ट पर आती और जाती थीं, लेकिन अब एकमात्र एयरलाइंस का एटीआर-72 विमान यहाँ से उड़ान भरता है। उसकी यात्री क्षमता 72 सीट की है, परंतु रनवे कम होने के कारण, दोनों तरफ ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ होने के कारण उसे अपनी यात्री क्षमता से आधे से भी कम यात्रियों को ले जाने अनुमति है। इसके कारण कुल्लू-दिल्ली प्रति यात्री किराया 18 हजार रुपये से 22 हजार रुपये तक रहता है। इस कारण यात्रियों को कुल्लू-दिल्ली हवाई यात्रा काफी महँगी पड़ती है।

महोदया, एटीआर विमान कंपनी का एक नया विमान एटीआर-42-600 विमानन क्षेत्र में उपलब्ध है, जो कि एटीआर विमान का एक नया मॉडल है, जिसकी क्षमता 48 यात्रियों को लाने/ले जाने की है। यह मॉडल छोटे रनवे पर उड़ान भरने के लिए सर्वोत्तम है।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से एटीआर 42-600 विमान का परिचालन प्रारंभ किए जाने के संबंध में Spicejet, Indigo Go Air आदि एयरलाइंस को आदेश दें और कुल्लू-भुंतर एयरपोर्ट से एटीआर 42-600 विमान का परिचालन प्रारम्भ करवाने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): I would like to draw your attention to the UDAN Scheme which was announced in the year 2016. I would also wish to draw your kind attention to its present status in the district Koppala, Karnataka.

When the scheme was announced, people were very happy as they could save their valuable time by taking connecting flight and thus make better use of their time for other work. With due regard, I wish to state that till today nothing has happened in this regard in Koppala, Karnataka.

(1700/PS/KN)

Madam, presently, Koppal has almost twenty running big industries. In Koppal, the setting up of toys cluster, being developed by Aequs company, is in the pipeline. The work has already started, creating employment opportunities for almost 25,000 people under the Atmanirbhar Bharat scheme.

A Memorandum of Understanding was sent to the Government of Karnataka in 2007. But till today, no communication has been received regarding the present status of the scheme. Due to this, the people of Karnataka and especially the people of Koppal, are very much disappointed.

I shall be very grateful if the authorities concerned are directed to get it done expeditiously for the betterment of the people of Koppal. The Ministry has given the deadline that by 2023, they will start the operation of airport.

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): अभी 7-8 माननीय सदस्य और बोलने वाले रह गए हैं। उनकी बात खत्म होने तक तकरीबन 10 मिनट का समय बढ़ा दिया जाए? क्या सभा की सहमति है?

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

माननीय सभापति : सभी के लिए एक-एक मिनट है।

श्री रितेश पाण्डेय।

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): Thank you, hon. Chairperson. India currently has two vaccines under emergency use approval -- one is Covidshield, developed by AstraZeneca and Oxford University, and the other is Covaxin, developed by Bharat Biotech. While the efficacy data of Covidshield

was established before any Government in the world approved it for its emergency use, the efficacy data of Covaxin is still pending and interim data of Phase-III trials may only be expected by March, according to the Chairman and Managing Director of Bharat Biotech.

Commencing the use of Covaxin without establishing its efficacy data in clinical trials has been criticised by the scientific community. It also explains the hesitancy of doctors and health workers to take the Covaxin shot. India aims to vaccinate 30 crore people by August, which means it needs to vaccinate over 10 lakh people a day. In three weeks since India's vaccine drive has begun, we have not even vaccinated 10 lakh people. Additionally, there have also been technical glitches with India's online vaccine platform, Co-WIN, which has further created obstacles in our ability to carry out the ambitious vaccination plan.

People's mistrust in the vaccine is a serious public health issue because vaccination is the only safe way to immunise the Indian population against the SARS-CoV-2 virus. This issue has become even more serious given that we have no definitive answer as to how long our body's antibodies will last and whether the antibodies prevalent in the Indian population will offer a robust enough protection against the novel strains of the corona virus circulating around the world. We must be prepared for a second or a third wave of the virus.

Hon. Chairperson, in the light of this, I would request the Government to take appropriate steps.

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही अविलम्बनीय विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत नानकमत्ता गुरुद्वारा है। ऐसी किंवदंती है कि वहां पर नानक जी को धरती ने आवाज दी कि यह गुरुद्वारा आपका है और उसी के बगल में नानक सागर है। अमृतसर के बाद इस पवित्र स्थल का ही नम्बर आता है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित करना अत्यावश्यक है। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको विकसित किया जाए। वाटर स्पोर्ट्स प्रारम्भ किए जाएं, ताकि जो देश-विदेश और दुनिया से लोग अमृतसर जैसी पवित्र जगहों के बाद यहां आते हैं, वे भरपूर तरीके से नानक सागर का आनंद ले सकें और इस पवित्रता में अपने को सराबोर कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बागपत जिले में बड़ौत सबसे बड़ा टाउन है और बहुत बड़ा शिक्षा का केन्द्र रहा है। वर्ष 1919 में जनता वैदिक कॉलेज बना। मेरे जैसे पता नहीं कितने ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, खिलाड़ी और प्रोफेशनल्स इसने पैदा किए। वर्ष 1960, 1970 और 1980 के दशक में विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के फील्ड में जब मैं

पढ़ता था, उस समय पूरे देश के बच्चे, ऐसा कोई राज्य नहीं था, वहां नहीं पढ़ते थे। वहीं के ग्रेजुएट्स, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बहुत जगहों पर वहां के प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उनका जो अल्मा-मेटर है, अभी तक वह यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। मेरा आपके माध्यम से कृषि और शिक्षा मंत्रालयों से यह निवेदन है कि इस जनता वैदिक कॉलेज को केन्द्रीय किसान विश्वविद्यालय बनाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि के बारे में ऐसा कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, जिससे यहां के किसानों को, किसानों के बच्चों को और न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि हरियाणा के बच्चों और आस-पास के प्रदेशों को भी उसका बहुत फायदा होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(1705/MM/SMN)

श्री मलूक नागर (बिजनौर): इस कोरोना काल में सरकार ने बहुत सारे राहत के पैकेज दिए हैं और बहुत सारी सुविधाएं देश में अलग-अलग विभागों के लिए की हैं। अगर किसानों को देखें तो लॉकडाउन के दौरान इनकी फसलें खेतों में खड़ी-खड़ी सड़ गयीं, दूध फट गए थे। इनका सर्वे कराकर इनकी भरपायी करवायी जाए। अभी जो किसान बिल आए हैं, उनके अनुसार इनवेस्टर नकद खरीदारी करेंगे। गन्ने की जब बिक्री की बात थी तो यह था कि उनको नकद पेमेंट मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ और देश में लाखों करोड़ बाकी हैं, उनको जल्द से जल्द दिलाया जाए। एक काम और है कि जिन किसानों के बच्चे नौकरियों पर थे, उनकी नौकरियां छूट गयीं, वे बेरोजगार हो गए। गांव स्तर पर सर्वे करवाकर, जिनकी नुकसान की भरपायी नहीं हुई है, नौकरियां भी छूट गयी हैं, बिजली बिल पर भी राहत नहीं मिली है, उसका सर्वे करवाकर सरकार तुरंत बेरोजगार बच्चों को नौकरियां उपलब्ध करवाएं। धन्यवाद।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): धन्यवाद सभापति महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र कटिहार है, जो बिहार में पड़ता है। यह क्षेत्र जूट उत्पादक है। बिहार के अधिकांश किसान जूट का उत्पादन करते हैं। वर्ष 1935 में कटिहार जिले में भारत सरकार के एक उपक्रम एनजेएमसी के द्वारा आरबीएम में जूट मिल चलायी जाती थी। यह जूट मिल 8 जनवरी, 2016 से बंद पड़ी है। इस जूट मिल में भारी संख्या में बोरे इत्यादि का उत्पादन होता था। इससे हजारों की संख्या में लोग सीधे रोजगार पाते थे। लाखों किसानों को जूट के क्रय-विक्रय से जूट की सही लागत मिल रही थी। भारत सरकार सभी तरह के उपक्रम और एमएसएमई को चला रही है। इसी तरह से कटिहार की जूट मिल को भी चलाया जा सकता है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि कटिहार जूट मिल की जो फिजीबिलिटी है और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, वह जूट मिल कभी भी चालू करवायी जा सकती है और वह चलने की स्थिति में है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि कटिहार जूट मिल को सरकार स्वयं चलाए या आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाया जा सकता है। दुर्भाग्य से यह जूट मिल प्रबंधन की गलती के कारण नहीं चल सकी और बंद थी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कटिहार जूट मिल को चलाया जाए। इससे किसानों को फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कटिहार जिला अकांक्षी जिला है, इससे उसका और बिहार का विकास होगा। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अफजाल अनसारी (गाजीपुर): सभापति महोदया, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ताकि आप संसदीय कार्यमंत्री को इस संबंध में दिशा-निर्देश दें।

महोदया, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के अनुरूप जो गाइडलाइंस तय हुई हैं, जो बजट गया है और जो काम हो रहे हैं, उनकी समीक्षा के लिए पूरे देश में जनपद स्तर पर दिशा कमेटीज बनी हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे विश्व में कोरोना काल में सारी व्यवस्थाएं ठप्प रहीं। हमारे देश में भी ऐसा ही रहा। अब जबकि बहुत हद तक इस सबसे कुछ उभरा जा चुका है, इस दौरान दिशा कमेटी की बैठकें कुछ जनपदों में हो रही हैं, लेकिन कुछ जनपदों में ऐसा लगता है कि एजेंडे से ही हटा दिया गया है। कैसे पता चलेगा कि हमारे विभागों के अधिकारीगण, जो बजट गया, उस पैसे का किस तरह से उपयोग किया गया? जनता में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। जनप्रतिनिधि जवाबदेह हैं। लेकिन जब उनके बीच में जाइए तो तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं।

माननीय सभापति (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): आप क्या चाहते हैं, वह बोलिए।

श्री अफजाल अनसारी (गाजीपुर): मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन सरकारी योजनाओं का बजट जनपद में गया है, उनकी समीक्षा के लिए दिशा की बैठक नियमों के अनुसार आहूत की जाए। मैं गाजीपुर से आता हूं और अभी तक मात्र एक बार दिशा की बैठक हुई है।

माननीय सभापति : आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गयी है।

श्री रमेश बिन्द।

(1710/MM/SNB)

श्री रमेश बिन्द (भदोही): महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से चुनकर आता हूं और भदोही कालीन नगरी के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है।

महोदया, पूरे प्रदेश में सफाईकर्मियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन किसी कारणवश हमारे जिले में सफाईकर्मियों की नियुक्ति नहीं हो पायी है। जिसके कारण लगभग तीन महीने से जिला मुख्यालय पर सफाईकर्मियों का धरना-प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से आप से मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार से सफाईकर्मियों की नियुक्ति करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे दिल्ली के कुछ युवा और युवतियों के संबंध में विशेष रूप से बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

महोदया, सिंगापुर सरकार के सहयोग से दिल्ली में एक विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र जौनपुर में बनना था। वर्ष 2013 में तब की मुख्यमंत्री, जिनका ट्रेंड बना हुआ था कि केवल वोट के लिए राजनीति करनी है, …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) देना है। वर्ष 2013 में सिंगापुर की विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र बनाने वाली एजेंसी को परमिशन दे दी गयी। 2 जुलाई 2012 को मंत्रीमंडल की बैठक करके उसकी मंजूरी प्रदान कर दी गयी। उस पर दोनों देशों का समझौता हो गया और हस्ताक्षर भी हो गए। वर्ष 2013 में विधान सभा के चुनाव होने थे, इसलिए लोगों को गुमराह करने के

लिए दोनों देशों के संबंधित संस्थानों तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा तीन वर्ष की अवधि वाला एक संदार्थ हस्तांतरित किया गया। जौनपुर गांव की 37 एकड़ जमीन प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग को ट्रांसफर कर दी गयी, जिसका कब्जा 18 सितम्बर को तकनीकी शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद वह सरकार नहीं आ पायी। 24 दिसम्बर को राष्ट्रपति शासन था और लोक सभा के चुनाव के बाद, तब 24 दिसम्बर, 2014 को शहरी विकास मंत्रालय में जो उस काम को देख रहे थे, उनसे उस भू भाग को परिवर्तित करवार स्टेट्स ऑफ लैण्ड यूज ट्रांसफर संबंधित अधिसूचना जारी करवा दी और 3.28 करोड़ रुपये जौनपुर की ग्राम सभा के खाते में जमा करवा दिए।

मैडम, उसके बाद एक नये विशेष प्राणी की सरकार आ गयी। मार्च, 2015 में तब के मुख्यमंत्री ने, चूंकि लोक सभा के चुनाव आने थे, उसकी मंजूरी दे दी गयी। लेकिन मंजूरी के बाद दिखावे के लिए 2.74 करोड़ रुपये बाउंड्री के लिए अलॉट कर दिए। उसके बाद 254 करोड़ रुपये की सहमति तो दे दी, लेकिन चुनाव के बाद वे उसको भूल गए, क्योंकि रूरल बेल्ट के नौजवानों को रोजगार न मिल जाए और उनको याचक बनाकर रखा जाए। राजनीति से प्रेरित होकर उस कौशल केन्द्र का, जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने एमएसएमई के माध्यम से, कौशल विकास योजना के माध्यम से, नौजवानों को रोजगार मिल जाए, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रूरल बेल्ट के लोगों से एनेमिटी रखते हुए, क्योंकि ज्यादातर वहां के रूरल बेल्ट के लोगों ने वोट नहीं दिया, उस कौशल विकास केन्द्र का काम प्रारम्भ नहीं करवा रहे हैं। उन बच्चों को याचक न रखा जाए। टेक्निकल एजुकेशन लेकर दिल्ली देहात के बच्चे एजुकेटेड हो जाएं। ले. गवर्नर के माध्यम से उसको तुरंत चालू करवाया जाए। धन्यवाद।

1713 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): अध्यक्ष जी, आज बजट सैशन के फर्स्ट पार्ट का आखिरी दिन है। कुदरत की आपदा होती है, जिसकी वजह से लोग बेघर हो जाते हैं। आज पंजाब के लाखों लोग भी बेघर हुए हैं। सर्दी निकल गई है और अब गर्मी आने वाली है। कोरोना, डेंगू और बहुत-सी बीमारियां मौसम बदलने के साथ आएंगी। आपके द्वारा सरकार से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इन लाखों लोगों से सरकार किसी भी तरीके से बातचीत करके उन्हें घर भेजे, क्योंकि यह हमारी रिस्पोंसिबिलटी है।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, वर्ष 2020 कोरोना काल के कारण पूरा निकल गया। अब 2021 में वैक्सीन आने की वजह से कुछ नई उम्मीद बनी। इंग्लैंड का जो म्यूटेंट स्ट्रेन आया, उसे लेकर बहुत विवाद था, लेकिन हमारे दोनों वैक्सीन उस पर कामयाब रहे। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि अभी साउथ अफ्रीका का स्ट्रेन आया है, जो अमरीका सहित तीन देशों में कोरोना की बीमारी फैला रहा है। अमरीका में यह देखा गया कि उस पर यह वैक्सीन कामयाब नहीं हो रही है। भारत बॉयोटेक का बहुत ही अच्छा वैक्सीन है। मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध रहेगा कि भारत बॉयोटेक और आईसीएमआर द्वारा जो वैक्सीन बना है, उसके सीरा को अफ्रीका भेजा जाए और अफ्रिकन स्ट्रेन पर बॉयोटेक कितना कामयाब है, इसकी जांच कराई जाए। जिससे कि भारत जो पूरी दुनिया में वैक्सीन का सैंटर बना हुआ है, अफ्रीका के नागरिकों को भी मदद कर सके और यह स्ट्रेन भारत में भी न आए, इसके लिए भी मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना

चाहूंगा। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री, भारत बॉयोटेक के वैक्सीन से प्रोड्यूस सीरा है, उसे अफ्रीका भेजकर अफ्रीकी स्ट्रेन की जांच कराएं, क्योंकि अमेरिकन वैक्सीन उस पर कुछ भी कामयाब नहीं हो पा रही है।

(1715/GG/RU)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय बदलना चाहती हूँ और यह विषय आशा की किरण, जो एक शेल्टर होम है दिल्ली के रोहिणी इलाके में। यह इकलौता शेल्टर होम है, जो मानसिक रूप से पीड़ित लोगों के लिए दिल्ली सरकार चलाती है। इसमें जो रहने वाले लोगों की क्षमता है, वह पांच सौ के आसपास है, लेकिन यहां पर नौ सौ से अधिक लोग हैं और जो व्यवस्थाएं वहां होनी चाहिए, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। शौचालयों से लेकर अन्य प्रावधानों की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन लोगों की मृत्यु यहां पर बहुत अधिक संख्या में हो रही है। तकरीबन 163 स्टाफ की यहां पर कमी है। इन सबके रहते हुए चाहे शौच है, चाहे उन रोगियों की देखभाल का काम है, यह बहुत कठिन काम होता है। इसके लिए ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत है। तो ऐसे में जो भी आर्थिक या मानव संसाधनों की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार पर्याप्त रूप से उसका प्रावधान करे। ताकि ऐसे रोगियों की, जिनके परिवार नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, एक संवेदनशीलता का प्रतीक हो। लेकिन यहां पर तो दिल्ली के मालिक असंवेदनशील हैं और वह सबको दिखाई दे रहा है। खास तौर पर ऐसे मानसिक रोगियों तक के लिए ये प्रावधान नहीं कर पा रहे है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिन्द।

माननीय अध्यक्ष: अब तो कोई वक्ता बाकी नहीं बचा है?

अनेक माननीय सदस्य: जी नहीं।

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
Shri Om Prakash Rajenimbalkar	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri B. B. Patil Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Bhavana Gawali (Patil)	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Prakash Rajenimbalkar Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Vinayak Bhaurao Raut	Shri Shrirang Appa Barne Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Prakash Rajenimbalkar
Shri Manish Tewari	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Krupal Balaji Tumane	Shri B. B. Patil Shri Om Prakash Rajenimbalkar Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Malook Nagar Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Shrirang Appa Barne	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Om Prakash Rajenimbalkar Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Malook Nagar
Dr. Nishikant Dubey	Shri Gopal Shetty Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rajkumar Chahar Shri Krishnapalsingh Yadav Shri Santosh Pandey Shri Ram Swaroop Sharma Adv. Ajay Bhatt	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Dr. Pritam Gopinathrao Munde	Shri Saptagiri Sankar Ulaka Shri Gopal Shetty Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Jagdambika Pal	Prof. S.P. Singh Baghel Shri Vinod Kumar Sonkar Shri Ritesh Pandey Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Janardan Singh Sigriwal

	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Rahul Kaswan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ram Kripal Yadav	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. Sanjay Jaiswal Shri Kuldeep Rai Sharma
Dr. Bharati Pravin Pawar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Prof. S.P. Singh Baghel	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Riti Pathak	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Rahul Ramesh Shewale	Shri Om Prakash Rajenimbalkar
Dr. Sujay Vikhe Patil	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil
Shri Kapil Moreshwar Patil	Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri Tapir Gao Shri Ajay Misra Teni	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Unmesh Bhaiyyasaheb Patil	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri Janardan Singh Sigriwal Shri Subhash Chandra Baheria Shri Vinod Kumar Sonkar	Kunwar Pushpendra Singh Chandel

Shri Sanjay Seth	
Dr. R. K. Ranjan	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Syed Imtiaz Jaleel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Rama Devi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Anupriya Patel	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Annpurna Devi	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shrimati Ranjeeta Koli	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kodikunnil Suresh	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Hibi Eden	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Rajmohan Unnithan	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Ramshiromani Verma	Shri Kuldeep Rai Sharma Shri Malook Nagar
Shri N.K. Premachandran	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri B. Manickam Tagore	Shri Kuldeep Rai Sharma
Shri Kuldeep Rai Sharma	Shri Malook Nagar
Shri Ritesh Pandey	Shri Malook Nagar
Shri Afzal Ansari	Shri Malook Nagar

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 को दोपहर चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1718 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 08 मार्च 2021 / 17 फाल्गुन, 1942 (शक)
के चार बजे तक के लिए स्थगित हुई।